mic Advisory Committee has since been given;

(b) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor; and

(c) whether AIKVTA has demanded representation to the tune of 25 per cent of its membership strength; if so, Government's reaction thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT (SHRI CHIMANBHAI MEHTA): (a) and (b) The Government is firmly committed to bringing about the representation of employees on the Kendriya Vidyalaya Sangathan and its Board of Governors. Modalities are being worked out.

(c) Yes, Sir. At present the modalities of representation e.g. whether by ballot, or verification of membership of Association, or any other suitable democratic method are being considered, after which the percentage of representation can be finalised.

National Defence Programme for Students

*376. SHRI SURESH KALMADI: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a working group on youth has suggested a National defence programme for students;

(b) whether Government have accepted the suggestion; and

(c) if so, what are the details in this regard and by when the programme would be implemented?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT (SHRI CHIMBANBHAI MEHTA): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) The suggestion is under consideration, in consultation with concerned experts and agencies.

महाराष्ट्र में थाणे स्थित "नेशनल आर्गेनिक केमिकल इन्डस्ट्रीज का" विस्तार

*377. **श्री विश्वासराव रामराव पाटिल:** क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र में थाणे स्थित "नेशनल आर्गेनिक केमिकल इन्डस्ट्रीज" के विस्तार से संबंधित प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है ;

(ख) यदि हां, तो इस संयंत्र के विस्तार का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ने की सम्भावना है ;

(ग) क्या सरकार को इस विस्तार कार्य के विरुद्ध कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउतराव) : (क) परियोजना प्राधिकारियों को आशय पत्र इस शर्त पर दिया गया है कि कम्पनी पर्यावरणीय और प्रदूषण की दृष्टि से पर्यावरण और वन मंत्रालय से मंजूरी लेगी और इस मंजूरी के अनुसार सभी आवश्यक अपेक्षाओं का पालन करेगी । परियोजना प्रस्तावकों से अनुरोध किया